भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 124

उत्तर देने की तारीख 3 फरवरी, 2025

सोमवार, 14 माघ 1946 (शक)

औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल को मजबूत करना

124. श्री दामोदर अग्रवालः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि हाशिए पर धकेले गए और वंचित समुदायों को उक्त पहल से लाभ मिले;

(घ) क्या सरकार अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भविष्य में उक्त पहल का विस्तार करने का इरादा रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) जी हां। प्रधानमंत्री के रोजगार और कौशल पैकेज के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2024 में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य हब-एंड-स्पोक व्यवस्था के माध्यम से 1,000 आईटीआई को उन्नत करना है, जो राज्य सरकारों और उद्योग सहयोग से परिणामोन्मुखीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। बजट घोषणा के अनुसार, इस स्कीम के

अंतर्गत पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा, तथा भारत की अर्थव्यवस्था की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने और औद्योगिक मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए तैयार कौशल कार्यबल बनाने की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।

(ग) इस स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस पहल से सीमांत और वंचित समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ) केंद्रीय बजट 2024 में घोषित स्कीम के अनुसार, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के 20 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों को पांच वर्षों की अवधि में लाभ मिलेगा। यद्यपि इस स्कीम की अवधि पांच वर्ष है, लेकिन प्रस्तावित नई स्कीम के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का उन्नयन, क्षमता-निर्माण पहल, उद्योग संरेखण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे प्रस्तावित हस्तक्षेप स्कीम अवधि से आगे भी उन्नत कौशल प्रशिक्षण को समर्थन प्रदान करते रहेंगे।

*****